समावेशन को बढ़ाएगा जेंडर बजट

***

3 जुलाई, 2025
नई दिल्ली

Key Takeaways

- The purpose of Gender Budgeting is to track spending and services to make sure women's needs are included and to improve their access to public resources.
- Gender Budget allocation: % increase in total budget from **5.46% in 2014-15 to 8.86% in 2025-26**; outlay increase of 4.**5x from ₹0.98 lakh crore in 2014-15 to ₹4.49 lakh crore** in 2025-26.
- The Gender Budget framework includes a three-part structure; Part A (100% women specific schemes), Part B (schemes with 30-99% allocation for women) and Part C (schemes with below 30% allocation towards women).
- Ten ministries allocate 30%+ budgets to gender initiatives, led by-

Ministry	%
Ministry of Women and Child Development	81.79%
Dept. of Rural Development	65.76%
Dept. Food & Public Distribution	50.92%

- Gender Budgeting Knowledge Hub portal, launched in June 2025 by Ministry of Women and Child Development, centralizes coordination across government entities.

परिचय

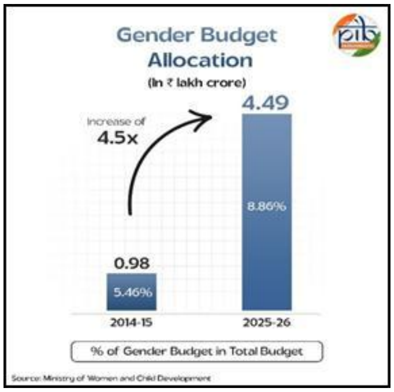

भारत में लैंगिक बजट के लिए वर्ष 2014-15 से 2025-26 तक आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। परिव्यय वर्ष 2014-15 में 0.98 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 4.49 लाख करोड़ रुपए हो गया है, केंद्रीय बजट में लैंगिक बजट का प्रतिशत हिस्सा वित्त वर्ष 2025-26 में 8.86 प्रतिशत तक बढ गया है, जो 2014-15 में 5.46 प्रतिशत था। यह

सार्वजनिक व्यय के माध्यम से लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने के सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

भारत ने वर्ष 2005-06 में लैंगिक बजट स्टेटमेंट की शुरुआत करके सरकारी बजट और खर्च को महिलाओं के लिए अधिक न्यायसंगत और सहायक बनाने के अपने प्रयासों में एक विशेष उपलब्धि प्राप्त किया। इसने लैंगिक दृष्टिकोण से सार्वजनिक संसाधन आवंटन की जांच करने के लिए देश की प्रतिबद्धता को चिह्नित किया। यह माना जाता है कि राष्ट्रीय बजट समाज के सभी वर्गों को समान रूप से प्रभावित नहीं करते हैं, इसलिए महिलाओं की विकासात्मक जरूरतों को सरकारी खर्च में पर्याप्त ध्यान देने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

> In June 2025, the Ministry of Women and Child Development organised a National Consultation on Gender Budgeting, during which the 'Gender Budgeting Knowledge Hub' portal was launched. The Hub is a digital repository of all information related to gender budgeting processes, intended for use by central and state government ministries/departments, as well as other stakeholders

लैंगिक बजट में तेज़ी आ रही है क्योंकि अधिकृत मंत्रालय और विभाग लिंग मुद्दों के बारे में जागरूक हो रहे हैं और लिंग-संवेदनशील दृष्टिकोण के साथ अपने कार्यक्रमों और योजनाओं की समीक्षा करना शुरू कर रहे हैं। यह विश्लेषणात्मक उपकरण न केवल एक लेखा अभ्यास के रूप में कार्य करता है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए एक रणनीतिक तंत्र के रूप में कार्य करता है कि महिलाओं की ज़रूरतों को सभी सरकारी कार्यों में शामिल किया जाए, जाँच की जाए कि क्या सेवाएं महिलाओं तक पहुंच रही हैं, और इसका उद्देश्य भारत की विकास योजनाओं में सार्वजनिक संसाधनों तक महिलाओं की पहुँच में सुधार करना है।

भारत के लैंगिक बजट ढांचे के घटक

लैंगिक बजट को दो भागों में विभाजित किया गया है - उन योजनाओं के लिए बजट प्रावधान जो मुख्य रूप से महिलाओं के लाभ के लिए हैं।

- भाग-क में उन योजनाओं का विवरण दिया गया है जिनमें 100 प्रतिशत प्रावधान महिलाओं के लिए है।
- भाग-ख उन योजनाओं को दर्शाता है जहां महिलाओं के लिए आवंटन कुल प्रावधान का कम से कम 30 प्रतिशत है।
- वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में, भाग-ग को प्रावधान के 30 प्रतिशत से कम महिलाओं और लड़कियों के लिए आवंटन वाली योजनाओं के रूप में शामिल किया

गया था। लैंगिक बजट विवरण में भाग-ग को शामिल करने से सरकार द्वारा महिलाओं के लिए आवंटन और लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को समग्र रूप से प्रतिबिंबित करने की उम्मीद है।

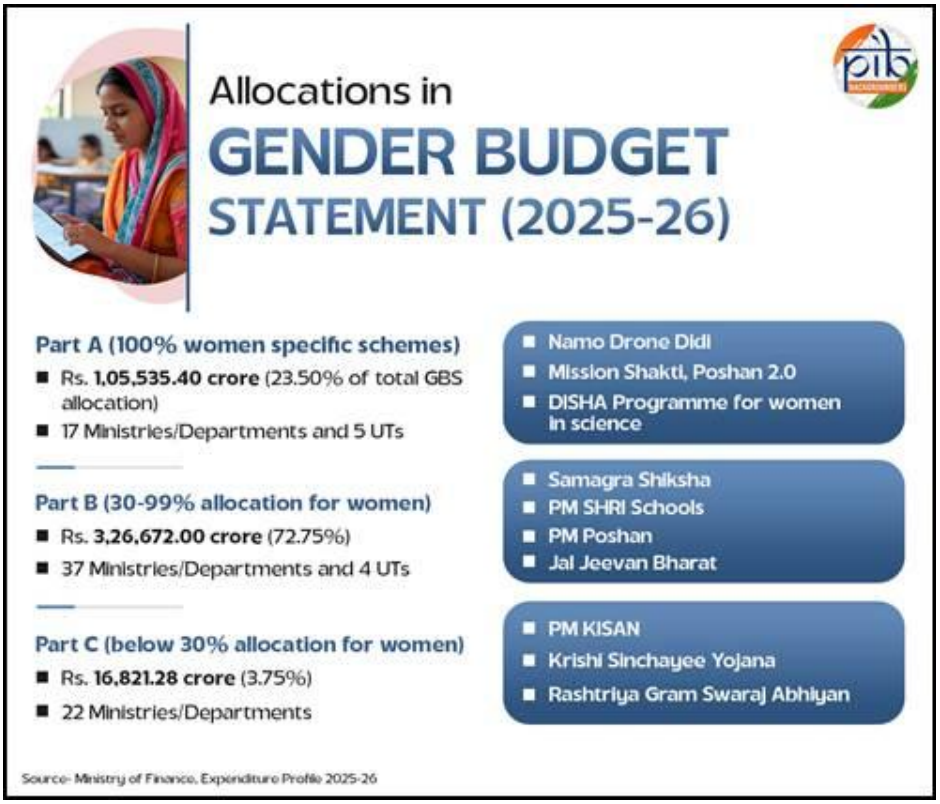

भारत में लैंगिक बजट का विकास

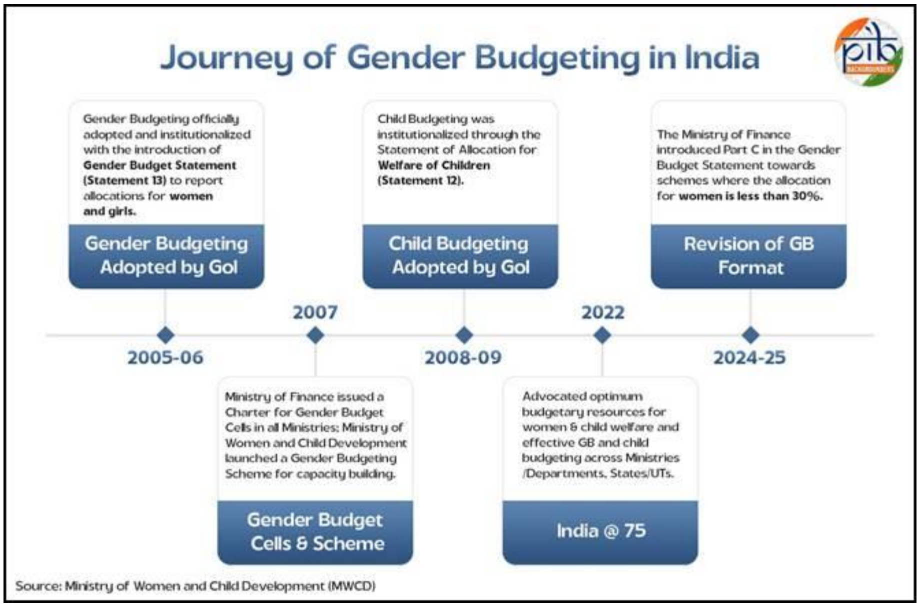

लैंगिक बजट: केंद्रीय बजट वर्ष 2025-26 - व्यय विवरण

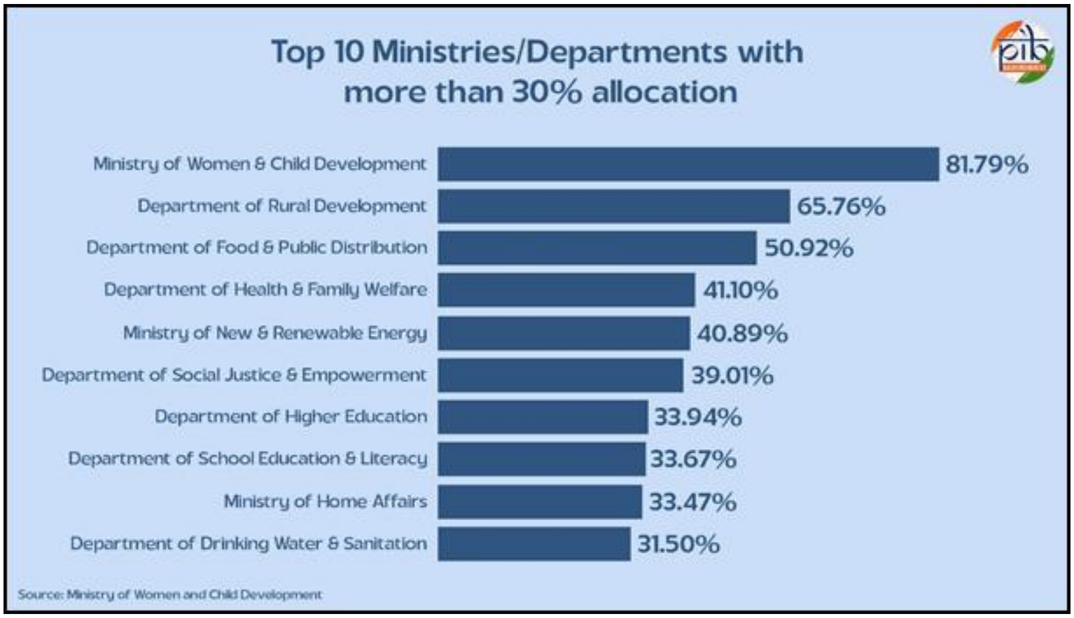

शीर्ष 10 मंत्रालय/विभाग जिन्होंने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लैंगिक बजट में अपने आवंटन का 30 प्रतिशत से अधिक हिस्सा देने की सूचना दी है:

लैंगिक बजट: सकारात्मक रुझान

ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के एक रिपोर्ट के अनुसार, जिसका शीर्षक है- '*भारत, बांग्लादेश और रवांडा में लिंग-उत्तरदायी बजट: एक तुलना*' (जुलाई 2020), भारत में लैंगिक बजट की शुरूआत एक सकारात्मक प्रवृत्ति दिखाती है:

- भारत ने राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर लैंगिक-उत्तरदायी बजट (जीआरबी) को संस्थागत रूप दिया है, तथा मंत्रालयों और विभागों में लैंगिक बजट प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं।

- केंद्रीय बजट में लैंगिक बजट विवरण (जीबीएस) को अनिवार्य रूप से शामिल करने से महिलाओं और लड़कियों के लिए आवंटन की नियमित जांच सुनिश्चित होती है।

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मैनुअल, हैंडबुक और प्रशिक्षण जैसी क्षमता निर्माण पहलों ने लैंगिक बजट में तकनीकी विशेषज्ञता को मजबूत किया है।

- कई राज्यों ने लैंगिक बजट विवरण को अपनाया है, जिससे विकेन्द्रीकृत और क्षेत्र-विशिष्ट लैंगिक हस्तक्षेप को बढ़ावा मिला है।
- लैंगिक-आधारित आंकड़ों को एकत्रित करने और परिणामों की निगरानी करने पर जोर दिया जा रहा है, तथा इनपुट-आधारित लेखांकन से आगे बढ़कर प्रभाव आकलन पर जोर दिया जा रहा है।
- पिछले कुछ वर्षों में लैंगिक बजट आवंटन में लगातार वृद्धि हुई है, जो लैंगिक समानता के प्रति बढ़ती वित्तीय प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- लैंगिक बजट विवरण ने नई महिला-केंद्रित योजनाओं के डिजाइन को प्रभावित किया है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण बढ़ा है।

ये रुझान सामूहिक रूप से सार्वजनिक व्यय और नीति नियोजन में लैंगिक विचारों को मुख्यधारा में लाने में देश की प्रगति को दर्शाते हैं।

निष्कर्ष

भारत में लैंगिक बजट एक परिवर्तनकारी शासन सुधार का प्रतिनिधित्व करता है जो गहरी जड़ें जमाए हुए संरचनात्मक असमानताओं को दूर करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए महज संसाधन आवंटन से आगे बढ़ता है। वित्त वर्ष 2025-26 में लैंगिक बजट आवंटन में 6.8 प्रतिशत से 8.86 प्रतिशत तक की उल्लेखनीय वृद्धि, एक व्यापक तीन-भागीय ढांचे के विकास और मिशन शक्ति के शुभारंभ के साथ, सभी सरकारी गतिविधियों में लैंगिक चिंताओं को मुख्यधारा में लाने के लिए भारत की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। *जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल* की स्थापना और लैंगिक पहलों के लिए अपने बजट का 30 प्रतिशत से अधिक आवंटित करने वाले दस प्रमुख मंत्रालयों की सक्रिय भागीदारी साक्ष्य-आधारित, लैंगिक-उत्तरदायी नीति निर्माण की दिशा में एक आदर्श बदलाव का संकेत देती है। नियोजन, बजट और कार्यान्वयन के हर पहलू में जेंडर लेंस को शामिल करके, भारत खुद को लैंगिक-उत्तरदायी शासन में एक ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित कर रहा है, जो एक अधिक न्यायसंगत और समावेशी समाज का मार्ग प्रशस्त कर रहा है जहाँ हर महिला अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर सकती है।

संदर्भ :

वित्त मंत्रालय:

- https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/vol1.pdf
- https://www.indiabudget.gov.in/budget2016-2017/ub2016-17/eb/stat20.pdf

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय:

- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2098912
- https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailmaspx?PRID=2137727
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2098912
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2094929
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1795471
- https://missionshakti.wcd.gov.in/gender-budgeting/about
- https://missionshakti.wcd.gov.in/public/documents/gbdocuments/17099660571749707051.pdf (पृष्ठ 1)

ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन:

- https://www.orfonline.org/public/uploads/posts/pdf/20230719005537.pdf

  (भारत, बांग्लादेश और रवांडा में लिंग-उत्तरदायी बजट: एक तुलना - 2020)

पीडीएफ फाइल के लिए यहां क्लिक करें

***

एमजी/केसी/एचएन/एसके

(Backgrounder ID: 154811)